



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2005/चैत्र 14, 1927

No. 350]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2005/CHAITRA 14, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2005

का.आ. 499(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1985 की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिकरण गठित किया, उसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में रखा और श्री जनक दीगल, भा.प्र.से. (एजीएमयूटी : 1985) को उक्त अधिकरण में नियुक्त करते हुए दिनांक 2 फरवरी, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 502(अ) द्वारा यह निदेश दिया गया कि वह, अंतर द्वीप नाविक संघ तथा अन्य के आवेदन में और वर्ष, 2004 की रिट याचिका सं. 120 से उत्पन्न हुए विवाद को निबटाने के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर अधिकरण का अधिनिर्णय केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करें।

जबकि, श्री जनक दीगल ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2005 के पत्र में सुनामी के कारण एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हुई अपनी कठिनाइयां बताई हैं जिसने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को 30 अप्रैल, 2005 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। सुनामी ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है।

श्री जनक दीगल के अनुरोध पर विचार करके केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त अधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु उसका कार्यकाल, एतद्वारा 30 अप्रैल, 2005 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

[फा. सं. एस एस-14017/11/2004-एसवाई-II]

सुशील कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Shipping)****(SHIPPING WING)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th April, 2005

S.O. 499(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1985 constituted a Tribunal with Headquarters at Port Blair appointing Shri Janak Digal, IAS (AGMUT : 1985) to the said Tribunal with the direction to submit the Award of the Tribunal to the Central Government within one month from the date of publication of the Notification, for settling the dispute raised in the application of Inter-Island Seamen Union and another, arising from Writ Petition No. 120 of 2004, vide Notification No. S.O. 502(E) dated 2nd February, 2005.

Whereas Shri Janak Digal vide his letter dated 21st February, 2005 has explained his difficulties in submitting the report within one month due to tsunami which severely affected the Andaman and Nicobar Islands, and has requested for extension of time for submission of his report upto 30th April, 2005.

Having considered the request of Sri Janak Digal the Central Government hereby decides to extend the tenure of the Tribunal upto 30th April, 2005 for submission of report to the Central Government.

[F. No. SS-14017/11/2004-SY II]

SUSHEEL KUMAR, Jt. Secy.